



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 19, 2000/आषाढ़ 28, 1922

No. 99]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 19, 2000/ASADHA 28, 1922

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2000

(साधारण बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2000

फा. सं. बी. वि. वि. प्रा./वि/7/2000.— प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 और धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा पुनर्बीमा) विनियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं: इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अभिप्रेत है;

(1)

(ख) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) “अध्यर्पण” से ऐसे बीमाकर्ता द्वारा, जिसने मूल बीमाकृत को पालिसी जारी की थी, पुनर्बीमाकर्ता को दिया गया बीमा का यूनिट अभिप्रेत है और, तदनुसार, कोई अध्यर्पण, पुनर्बीमा संविदा में सहमत किए गए अनुसार, संपूर्ण एकल जोखिम या उसका भाग, परिभाषित पालिसियां या कारबार के परिभाषित प्रभाग हो सकेगा;

(घ) “जोखिम पुनर्बीमा” से ऐसी एकल पालिसी के, जिसमें पृथक् रूप से अध्यर्पण के लिए बातचीत की गई है, भाग या संपूर्ण का पुनर्बीमा अभिप्रेत है और यह कि पुनर्बीमाकर्ता और बीमाकर्ता के पास प्रत्येक व्यक्ति निवेदन को स्वीकार करने या इंकार करने का विकल्प है;

(ङ) “भारतीय पुनर्बीमाकर्ता” से ऐसा बीमाकर्ता अभिप्रेत है, जो अनन्य रूप से पुनर्बीमा कारबार चला रहा है और इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है;

(च) “पूल” से बीमा या पुनर्बीमा की ऐसी कोई संयुक्त निम्नांकन संक्रियाएं अभिप्रेत है, जिसमें भाग लेने वाले, सभी लिखित कारबार में पूर्व अवधारित और नियत हित की धारणा करते हैं,

(छ) “पुनः अध्यर्पण” से ऐसा संव्यवहार अभिप्रेत है, जिसके द्वारा पुनर्बीमाकर्ता, ऐसे पुनर्बीमा के, जिसे उसने पूर्व में ग्रहण किया है, संपूर्ण या भाग को किसी अन्य बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता का अध्यर्पित करता है;

(ज) “प्रतिधारण” से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे बीमाकर्ता अपने स्वयं के लेखा के लिए ग्रहण करता है। समानुपातिक संविदाओं में प्रतिधारण पालिसी सीमा का प्रतिशत हो सकेगा। हानि संविदाओं से अधिक, प्रतिधारण एक हानि की रकम है;

(झ) “संधि” से बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता के बीच प्रायः एक वर्ष या अधिक के लिए किया गया ऐसा पुनर्बीमा करार अभिप्रेत है, जो कारबार के किसी वर्ग या वर्गों को लागू तकनीकी विशिष्टियां या वित्तीय निबंधन अनुबद्ध करता है;

(ण) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) या साधारण बीमा कारबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 57) या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) या उनके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, क्रमशः वहीं अर्थ होंगे, जो उन्हें, यथास्थिति, उन अधिनियमों या नियमों में समनुदेशित किए गए हैं।

अध्याय II

3. पुनर्बीमा इंतजामों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:—

(1) पुनर्बीमा कार्यक्रम निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निरंतर उनसे मार्गदर्शन लेता रहेगा:

(क) देश के भीतर प्रतिधारण को अधिकतम करने के लिए;

(ख) पर्याप्त क्षमता विकसित करने के लिए;

(ग) उपगत पुनर्बीमा लगतों के लिए सर्वोत्तम सम्भव संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए;

(घ) कारबार के प्रशासन को सरलीकृत करने के लिए।

(2) प्रत्येक बीमाकर्ता अपना वित्तीय सामर्थ्य और कारबार की मात्रा के अनुरूप अधिकतम सम्भव प्रतिधारण बनाए

रखेगा। प्राधिकारी किसी बीमाकर्ता से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपनी प्रतिधारण पालिसी को उचित ठहराए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय बीमाकर्ता, किसी विदेशी बीमाकर्ता का प्रतिनिधि मात्र नहीं है, उसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(3) प्रत्येक बीमाकर्ता भारत में लिखित बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए प्रत्येक पालिसी पर बीमा की गई राशि का ऐसा प्रतिशत भारतीय पुनर्बीमाकर्ता को अध्वर्पित करेगा जो प्राधिकारी द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 के भाग IV के उपबन्धों के अनुसार, विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) प्रत्येक बीमाकर्ता का पुनर्बीमा कार्यक्रम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ से प्रारम्भ होगा और प्रत्येक बीमाकर्ता, प्राधिकारी को आगामी वर्ष के लिए उसका बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से 45 दिन पहले जमा करेगा;

(5) प्रत्येक बीमाकर्ता, वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 30 दिन के भीतर प्राधिकारी को पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची और पुनर्बीमा इन्तजाम में उनके अंश के साथ प्रत्येक पुनर्बीमा सन्धि पर्व की फोटो प्रति और उस वर्ष की बाबत हानि कवर कवरनोट फाइल करेगा।

(6) प्राधिकारी किसी बीमाकर्ता के पुनर्बीमा कार्यक्रम की बाबत और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे;

(7) बीमाकर्ता, भारत से बाहर अपना पुनर्बीमा कारबार केवल ऐसे पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ करेगा, जिनके पास कारबार करने के वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष से गणना करके पिछले पांच वर्ष की अवधि से (स्टैंडर्ड एंड पूअर की) कम से कम ख ख ख रेटिंग या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग अभिकरण की समतुल्य रेटिंग हैं। अन्य पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ कारबार के लिए प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित होगा। बीमाकर्ता लायड सिंडीकेट के साथ भी पुनर्बीमा कर सकेंगे, लेकिन वे यह ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति सिंडीकेटों के साथ कारबार के ऐसे शेयर उस सीमा तक होंगे जो सिंडीकेट की क्षमता के अनुरूप हों।

(8) भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, अग्नि, समुद्री हल और अन्य वर्गों के पुनर्बीमा अधिशेष के लिए, सभी बीमाकर्ताओं के परामर्श से, ऐसे आधारों, सीमाओं और निबंधनों पर, जो सभी बीमाकर्ताओं के लिए उचित हैं, घरेलू पूल संगठित करेगा और भारत के भीतर वर्ष 1999-2000 के लिए प्राप्त स्तर के यथासंभव निकट कारबार के प्रतिधारण में सहायता करेगा।

(9) वर्गवार घरेलू पुनर्बीमा इन्तजाम का अधिशेष, बीमाकर्ता द्वारा स्वतंत्र रूप से, भारत से बाहर अध्वर्पित कुल पुनर्बीमा प्रीमियम के 10 को किसी एक पुनर्बीमाकर्ता को देने की सीमा के अधीन रहते हुए, उपविनियम (7) को अनुपालन करने वाले किसी पुनर्बीमाकर्ता को दिया जा सकता है जहां किसी विशिष्ट बीमा की बाबत किसी विशिष्ट पुनर्बीमाकर्ता को ऐसी सीमा से अधिक शेयर अध्वर्पित करना आवश्यक है, वहां बीमाकर्ता ऐसे अभ्यर्पण के कारण बताते हुए प्राधिकारी का विनिर्दिष्ट अनुमोदन ले सकता है।

(10) प्रत्येक बीमाकर्ता, ऐसे अभ्यर्पण को भारत से बाहर देने से पहले, अन्य भारतीय बीमाकर्ताओं को, जिसमें भारतीय पुनर्बीमाकर्ता भी सम्मिलित है, अपने जोखिम पुनर्बीमा और संधि अधिशेषों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करेगा।

(11) भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, उसके द्वारा प्राप्त आबद्धकर अभ्यर्पण का कम से कम 50, पोर्टफोलियो को समुचित हानि कवरों के आधिक्य से संरक्षित करने के पश्चात्, अभ्यर्पण करने वाले बीमाकर्ता को पुनः अध्वर्पित करेगा। ऐसा पुनः अभ्यर्पण मूल निबंधनों पर होगा और इसमें भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के लिए 2.5 से अनधिक अध्यारोही कमीशन जोड़ा जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्पण करने वाले बीमाकर्ता को पुनः अभ्यर्पण, उसके भारतीय पुनर्बीमाकर्ता को किए गए अभ्यर्पणों के समानुपातिक होगा।

(12) प्रत्येक बीमाकर्ता से यह अपेक्षित होगा कि वह प्राधिकारी को उसके वार्षिक लेखों के साथ उसके पुनर्बीमा संव्यवहार से सम्बन्धित आंकड़े ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करे जिन्हें प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे।

4. आवक पुनर्बीमा कारबार- प्रत्येक बीमाकर्ता के पास, जो आवक पुनर्बीमा कारबार करना चाहता है, आवक पुनर्बीमा कारबार के निम्नांकन के लिए एक सुपरिभाषित निम्नांकन पालिसी होगी। बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि पुनर्बीमा कारबार की स्वीकृति पर निर्णय ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिए जाएंगे जिनके पास आवश्यक जानकारी और अनुभव है। बीमाकर्ता, प्राधिकारी को उसकी निम्नांकन पालिसी पर टिप्पण फाइल करेगा जिसमें कारबार के वर्गों, भौगोलिक स्कोप, निम्नांकन सीमाओं और लाभ उद्देश्य का कथन होगा। बीमाकर्ता, जब निम्नांकन पालिसी में कोई परिवर्तन किया जाता है तब टिप्पण में परिवर्तनों को भी फाइल करेगा।

5. बकाया हानि उपबंध- (1) प्रत्येक बीमाकर्ता, प्रत्येक स्वीकृत पुनर्बीमा इन्तजाम के लिए दलालों/सीडेंटों से प्राप्त हानि जानकारी सलाहों के आधार पर, और जहां ऐसे सलाहें प्राप्त नहीं होती हैं वहां बीमांकन प्राक्कलन के आधार पर, बकाया दावों के लिए उपबंध करेगा।

(2) इसके अतिरिक्त, प्रत्येक बीमाकर्ता, उपगत किन्तु रिपोर्ट नहीं किए जाए (आई बी एन आर) दावों के लिए, इसके स्वीकृत पुनर्बीमा पोर्टफोलियो पर बीमांकन प्राक्कलन के आधार पर समुचित उपबंध करेगा।

एन रगाचारी, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/161/2000]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th July, 2000

(General Insurance—Reinsurance) Regulations, 2000

F. No. IRDA/Reg/7/2000.—

In exercise of the powers conferred by section 114A of the Insurance Act, 1938, sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:

CHAPTER I**PRELIMINARY****1. Short title and commencement :**

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (General Insurance - Reinsurance) Regulations, 2000.
- (2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. Definitions:

In these regulations, unless the context otherwise requires:

- a) 'Act' means the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999 (41 of 1999);
- b) 'Authority' means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- c) 'cession' means the unit of insurance passed to a reinsurer by the insurer which issued a policy to the original insured and, accordingly, a cession may be the whole or a portion of single risks, defined policies or defined divisions of business, as agreed in the reinsurance contract;

- d) 'facultative' means the reinsurance of a part or all of a single policy in which cession is negotiated separately and that the reinsurer and the insurer have the option of accepting or declining each individual submission;
- e) 'Indian re-insurer' means an insurer who carries on exclusively reinsurance business and is approved in this behalf by the Central Government;
- f) 'pool' means any joint underwriting operation of insurance or reinsurance in which the participants assume a predetermined and fixed interest in all business written.
- g) 'retrocession' means the transaction whereby a reinsurer cedes to another insurer or reinsurer all or part of the reinsurance it has previously assumed;
- h) 'retention' means the amount which an insurer assumes for his own account. In proportionate contracts, the retention may be a percentage of the policy limit. In excess of loss contracts, the retention is an amount of loss;
- i) 'treaty' means a reinsurance arrangement between the insurer and the reinsurer, usually for one year or longer, which stipulates the technical particulars and financial terms applicable to the reinsurance of some class or classes of business;
- j) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) or the General Insurance Business Nationalisation Act, 1972 (57 of 1972) or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), rules made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or rules as the case may be.

CHAPTER II

3. PROCEDURE TO BE FOLLOWED FOR REINSURANCE ARRANGEMENTS

- (1) The Reinsurance Programme shall continue to be guided by the following objectives to:
 - a) maximise retention within the country;
 - b) develop adequate capacity;
 - c) secure the best possible protection for the reinsurance costs incurred;
 - d) simplify the administration of business.
- (2) Every insurer shall maintain the maximum possible retention commensurate with its financial strength and volume of business. The Authority may require an insurer to justify its retention policy and may give such directions as considered necessary in order to ensure that the Indian insurer is not merely fronting for a foreign insurer.

- (3) Every insurer shall cede such percentage of the sum assured on each policy for different classes of insurance written in India to the Indian reinsurer as may be specified by the Authority in accordance with the provisions of Part IVA of the Insurance Act, 1938.
- (4) The reinsurance programme of every insurer shall commence from the beginning of every financial year and every insurer shall submit to the Authority, his reinsurance programmes for the forthcoming year, 45 days before the commencement of the financial year;
- (5) Within 30 days of the commencement of the financial year, every insurer shall file with the Authority a photocopy of every reinsurance treaty slip and excess of loss cover covernote in respect of that year together with the list of reinsurers and their shares in the reinsurance arrangement;
- (6) The Authority may call for further information or explanations in respect of the reinsurance programme of an insurer and may issue such direction, as it considers necessary;
- (7) Insurers shall place their reinsurance business outside India with only those reinsurers who have over a period of the past five years counting from the year preceding for which the business has to be placed, enjoyed a rating of at least BBB (with Standard & Poor) or equivalent rating of any other international rating agency. Placements with other reinsurers shall require the approval of the Authority. Insurers may also place reinsurances with Lloyd's syndicates taking care to limit placements with individual syndicates to such shares as are commensurate with the capacity of the syndicate.
- (8) The Indian Reinsurer shall organise domestic pools for reinsurance surpluses in fire, marine hull and other classes in consultation with all insurers on basis, limits and terms which are fair to all insurers and assist in maintaining the retention of business within India as close to the level achieved for the year 1999-2000 as possible. The arrangements so made shall be submitted to the Authority within three months of these regulations coming into force, for approval.
- (9) Surplus over and above the domestic reinsurance arrangements class wise can be placed by the insurer independently with any of the reinsurers complying with sub-regulation (7) subject to a limit of 10% of the total reinsurance premium ceded outside India being placed with any one reinsurer. Where it is necessary in respect of specialised insurance to cede a share exceeding such limit to any particular reinsurer, the insurer may seek the specific approval of the Authority giving reasons for such cession.
- (10) Every insurer shall offer an opportunity to other Indian insurers including the Indian Reinsurer to participate in its facultative and treaty surpluses before placement of such cessions outside India.

- (11) The Indian Reinsurer shall retrocede at least 50% of the obligatory cessions received by it to the ceding insurers after protecting the portfolio by suitable excess of loss covers. Such retrocession shall be at original terms plus an over-riding commission to the Indian Reinsurer not exceeding 2.5%. The retrocession to each ceding insurer shall be in proportion to its cessions to the Indian Reinsurer.
- (12) Every insurer shall be required to submit to the Authority statistics relating to its reinsurance transactions in such forms as the Authority may specify, together with its annual accounts.
4. Inward Reinsurance Business: Every insurer wanting to write inward reinsurance business shall have a well-defined underwriting policy for underwriting inward reinsurance business. The insurer shall ensure that decisions on acceptance of reinsurance business are made by persons with necessary knowledge and experience. The insurer shall file with the Authority a note on its underwriting policy stating the classes of business, geographical scope, underwriting limits and profit objective. The insurer shall also file any changes to the note as and when a change in underwriting policy is made.

5. Outstanding Loss Provisioning

- (1) Every insurer shall make outstanding claims provisions for every reinsurance arrangement accepted on the basis of loss information advices received from Brokers/ Cedants and where such advices are not received, on an actuarial estimation basis.
- (2) In addition, every insurer shall make an appropriate provision for incurred but not reported (IBNR) claims on its reinsurance accepted portfolio on actuarial estimation basis.

N. RANGACHARY, Chairperson

[No. ADVT.-3/4/Exty/161/2000]